4 अध्याय

मुद्रास्फीति

इस अध्याय में आप सीखेंगे किः

- मुद्रास्फीति का अर्थ, कारण, प्रकार व प्रभाव।
- मुद्रास्फीति पर नियंत्रणः मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति द्वारा।

परिचय (Introduction)

वर्तमान में देश के केन्द्रीय बैंक व सरकार के लिये सबसे अहम् विषय 'मुद्रास्फीति' के दर को इस प्रकार से बनाये रखना है जिससे देश का आर्थिक विकास भी होता रहे और आम जनता के बजट पर मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव भी न पड़े। अर्थात् मुद्रास्फीति एक ओर देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक है, वही आम जनता के लिए वस्तुओं और सेवाओं के महंगे होने से विशेषकर गरीब व मध्यम वर्ग नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगते है। चूंकि भारत में गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की अधिकता है, तो ऐसी स्थिति में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होने के नाते इस वर्ग का संरक्षण करना सरकार व केन्द्रीय बैंक के लिए अनिवार्य हो जाता है। इस अध्याय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुद्रास्फीति की बढ़ी हुई दरें एक ओर आम जनता के हित प्रभावित करती है वही मुद्रास्फीति की दर देश के आर्थिक विकास को गति देने में किस प्रकार सहायक है?

मुद्रास्फीति (Inflation)

- मुद्रास्फीति का अर्थ
- मुद्रास्फीति के कारण
- मुद्रास्फीति के प्रकार
- मुद्रास्फीति के प्रभाव
- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण

मुद्रास्फीति का अर्थ (Meaning of Inflation)

अर्थव्यवस्था में व्याप्त वह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है जब वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के सापेक्ष, मांग तेजी से बढ़ती है और इस स्थिति में मांग और आपूर्ति के मध्य अंतर बढ़ने से मूल्य वृद्धि होना स्वभाविक हो जाता है। यदि यह मूल्य वृद्धि सतत बनी रही तो इस स्थिति में मुद्रा की क्रय क्षमता में ह्रास देखने को मिलता है। अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं की सतत मूल्य वृद्धि, मुद्रा की क्रयक्षमता को कम कर देती है। परिणामस्वरूप मुद्रा, पहले की तुलना में कम वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर पाती है यह स्थिति 'मुद्रास्फीति कहलाती' है। आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति को 'महंगाई' कहा जाता है।

वस्तुओं और सेवाओं की मांग ↑ → वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति ↓ → मूल्य में सतत वृद्धि → रूपये की क्रय शक्ति ↓ = मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति के कारण (Reasons for Inflation)

मुद्रास्फीति का अर्थ जानने के बाद यह ज्ञात करना आवश्यक है कि वे कौन से कारक है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के लिऐ जिम्मेदार है। वे कारक निम्नवत् है—

- मांग प्रेरित स्फीति
- लागत प्रेरित स्फीति
- अन्य कारक

मांग प्रेरित स्फीति—जब वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण उनकी तेजी से बढ़ती **'मांग'** हो तो यह स्थिति ही **'मांग से प्रेरित स्फीति'** कहलाती है। यहाँ यह भी जानना अनिवार्य है कि मांग में वृद्धि के लिए कौन-कौन से कारक अनिवार्य है?

मांग में वृद्धि के कारण—अर्थव्यवस्था में तीव्रता से मांग बढ़ने के प्रमुख कारण निम्नवत् है:

- जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, मांग को तीव्रता से बढ़ाने में सहायक है।
- उपभोक्ता की व्यय योग्य आय बढ़ने से वह पहले की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेगा।
- अन्य देशों से पलायित होकर आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि भी मांग में वृद्धि करती है।
- बैंक यदि अपनी ब्याज दरों में कमी करते है तो आम जनता बैंकों से अधिक मात्रा में तरलता प्राप्त करेगे। यह बढ़ी हुई तरलता, मांग में वृद्धि करेगी।
- घाटे की वित्त व्यवस्था (केन्द्रीय बैंक द्वारा नये नोट निर्गमित करना) भी अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने में सहायक है, जो मांग में वृद्धि करती है।
- सरकार द्वारा कल्याणकारी उद्देश्यों से किये जाने वाले व्यय जैसे—वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्तियाँ, गरीब वर्ग को दी जाने वाली आर्थिक सहायता व भत्ते आदि भी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता की स्थिति बनाये रखने में सहायक होते है। यह अतिरिक्त तरलता मांग को बढ़ाने में सहायक है।
- कालेधन में वृद्धि भी मांग में वृद्धि करती है।

उपरोक्त कारक अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में सहायक है, यह स्थिति ही मांग से प्रेरित स्फीति (Demand Pull Inflation) कहलाती है।

लागत प्रेरित स्फीति—जब वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण उनकी उत्पादन लागत का बढ़ना हो तो यह स्थिति ही **'लागत से प्रेरित स्फीति'** कहलाती है। यहाँ यह भी जानना अनिवार्य हो जाता है कि वस्तुओं की लागत बढ़ने के क्या कारण है?

लागत बढ़ने के कारण—उत्पादन लागत बढ़ने के प्रमुख कारण निम्नवत् है—

- कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ाने में सहायक है।
- उत्पदक वर्ग के लिये मालगाड़ी के किरायों में वृद्धि, पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में वृद्धि व विद्युत प्रतियूनिट मूल्य वृद्धि, वस्तु के उत्पादन की लागत को स्वत: ही बढ़ा देती है।
- बैकों द्वारा ब्याज दर को बढ़ाने और सरकार द्वारा कर की दरों को बढ़ाने की स्थिति में भी उत्पादक वर्ग के लिये वस्तु की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत महंगी हो जाती है।

उपरोक्त कारक उत्पादक वर्ग की लागत को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। यह स्थिति ही लागत से प्रेरित स्फीति (Cost Pull Inflation) कहलाती है।

अन्य कारक—मुद्रास्फीति की दरो को बढ़ाने में अन्य कारक भी उत्तरदायी है जैसे—

- प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन प्रभावित होता है जो आपूर्ति पक्ष को प्रभावित करता है।
- दोषपूर्ण वितरण प्रणाली व उत्पादक वर्ग की अधिकतम लाभ कमाने की प्रवृत्ति उन्हें वस्तुओं की होल्डिंग करने के लिए प्रेरित करती है जिससे आपूर्ति, मांग के सापेक्ष कम रह जाती है।
- यदि उन वस्तुओं का निर्यात अधिक हो जाये जिनकी घरेलू बाजार में मांग अधिक है, तो यह स्थिति भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सहायक है।
- हड़ताले, तालाबन्दी, राजनीतिक अस्थिरता व जन आक्रोश भी आपूर्ति पक्ष को प्रभावित करते हैं।
- वैश्विकरण के इस दौर में जब सम्पूर्ण विश्व 'वैश्विक गाँव' में परिवर्तित हो रहा है। इस स्थिति में विश्व के किसी भी देश में कोई भी उथल-पुथल होती है, सम्पूर्ण विश्व उस उथल-पुथल से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा पाता। जैसे—ब्रेकजिट (2016-17), अमेरिका का आर्थिक संकट (2007-08)

मुद्रास्फीति के प्रकार (Types of Inflation)

प्रकृति के आधार पर मुद्रास्फीति के चार प्रकार होते है जो निम्नवत् है—

तालिका 4.1: प्रकृति के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार

मुद्रास्फीति के प्रकार	अर्थ	महत्वपूर्ण तथ्य
(i) अति मुद्रास्फीति	जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर इतनी तीव्र गति से बढ़े कि वहां की प्रचलित मुद्रा की क्रयक्षमता शीघ्रता से घटने लगें। इस स्थिति में प्रचलित मुद्रा आम जनता का विश्वास खोने लगे तथा सर्वत्र अशांति एवं असंतोष की स्थिति उत्पन्न होने लगे तो, यह स्थिति ही **अति मुद्रास्फीति (Hyper Inflation)** कहलाती है।	अफ्रीका महाद्वीप का देश जिम्बाब्वे में यह स्थिति देखने को मिलती है। हाल ही में द.अमेरिकी देश वेनेजुएला मे भी यह स्थिति देखने को मिलती है।
(ii) मंद मुद्रास्फीति	जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर बहुत मंद गति से बढ़े अर्थात् मूल्यों में वृद्धि बहुत धीमी गति से हो और लोगों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव नाममात्र का पड़े तो यह स्थिति ही **मंद मुद्रास्फीति (Creeping Inflation)** कहलाती है।	जिन अर्थव्यवस्थाओं में मांग और आपूर्ति के मध्य अंतर बहुत सीमित हो 'मंद मुद्रास्फीति' उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलती है जैसे—विकसित अर्थव्यवस्थाएँ।

(Continued)

तालिका 4.1: प्रकृति के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार *(Continued)*

मुद्रास्फीति के प्रकार	अर्थ	महत्वपूर्ण तथ्य
(iii) **द्रुत मुद्रास्फीति**	दौड़ती मुद्रास्फीति व मंद मुद्रास्फीति के मध्य की स्थिति को द्रुत मुद्रास्फीति कहते है। अर्थात् मुद्रास्फीति का दर न तो इतनी तीव्र गति से बढ़े की आम जनता का अपनी प्रचलित मुद्रा से विश्वास उठ जाये और न ही इतनी मंद गति से बढ़े कि आम जनता को मूल्य वृद्धि का एहसास ही न हो। यह स्थिति ही **चलती मुद्रास्फीति (Galloping Inflation)**की कहलाती है।	विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का यह प्रकार प्रचलित है।
(iv) **गतिहीन मुद्रास्फीति**	जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दर बने रहने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर हो जाये अर्थात् स्फीति के साथ-साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हो तो यह स्थिति **गतिहीन मुद्रास्फीति (Stagflation)** कहलाती है।	भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिहीन मुद्रास्फीति की स्थिति वित्तीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 में देखने को मिलती है जब मुद्रास्फीति की बढ़ी दर होने के बावजूद भी जीडीपी वृद्धि दर बहुत धीमी हो गयी थी।

मुद्रास्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)

मुद्रास्फीति के प्रभाव निम्नवत् है—

1. सकारात्मक प्रभाव,
2. नकारात्मक प्रभाव

1. **सकारात्मक प्रभाव**—मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्यों में सतत वृद्धि होती है, मूल्यों की यह वृद्धि उत्पादक वर्ग के लाभ को बढ़ा देती है जिससे उत्पादक वर्ग नये निवेश, नये उत्पादन व नये रोज़गार सृजित करता है। परिणामस्वरूप देश की जीडीपी, प्रतिव्यक्ति आय, बचत दर व पूंजीनिर्माण दर में वृद्धि देखने को मिलती है। उपरोक्त स्थितियाँ आर्थिक सुधार लाने के साथ-साथ सामाजिक स्थिति में सुधार लाती है जैसे—रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना, गरीबी, बेरोज़गारी व जनसंख्या वृद्धि दर के प्रतिशत में कमी लाना, साक्षरता दर को बढ़ाना आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देता है। ध्यान देने योग्य विषय यह भी है कि मुद्रास्फीति के कारण वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक सुधार दृष्टिगोचर होते है जैसे—देश के भीतर उत्पादन में वृद्धि भविष्य में देश के निर्यात बढ़ने व दूसरे देशों पर आयात की निर्भरता को कम करने में सहायक है जिससे एक ओर व्यापार शेष में सुधार व विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि देखने को मिलती है और वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की साख मजबूत हो जाती है। वैश्विक जगत में मजबूत साख, एफडीआई को आकर्षित करती है जिससे पुन: निवेश, उत्पादन, रोजगार सृजन, सरकारी राजस्व में वृद्धि दृष्टिगोचर होता है। साथ ही साथ देश की आधारभूत संरचना में युद्ध स्तरीय सुधार देखने को मिलते है। अंत में यह कहना अतिश्योक्त न होगा कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में सकारात्मक सुधार लाने में सक्षम है जिनमें सुधार करने में बहुत अधिक व्यय और दीर्घकालिक समयावधि लगता है।
2. **नकारात्मक प्रभाव**—मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभाव नि:संदेह अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने में सहायक है परन्तु मुद्रास्फीति के चलते आधारभूत वस्तुओं अर्थात् खाद्यान्न पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होने से सर्वाधिक गरीब व मध्यमवर्ग प्रभावित होते है। उनकी क्रय क्षमता क्षीण होने लगती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में देखे तो देश की कुल जीडीपी में बचत दर 33.0 प्रतिशत (2014-15 के अनुसार) है और इस प्रतिशत में सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र का है। अत: मूलभूत आवश्यकताओं वाली वस्तुओं की मूल्य वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से घरेलू क्षेत्र की बचत को कम कर देगी और वे बैंकों में न तो नयी बचत रखने के लिए प्रेरित होंगे बल्कि बैंकों में रखी अपनी बचतों को निकालने में तीव्रता दिखायेंगे। परिणामस्वरूप बैंकों में तरलता कम होने के चलते बैंक, उत्पादक वर्ग के लिए ऋण की दरों में वृद्धि करने के लिए मजबूर होंगे। यह स्थिति नये निवेश, उत्पादन व रोजगार सृजन को हतोत्साहित करने वाली है। अत: मुद्रास्फीति की यह स्थिति अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना प्रारम्भ कर देती है।

मुद्रास्फीति की इष्टतम दर

यहाँ पर यह प्रश्न उठना अनिवार्य है कि मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सक्षम है तो वहीं दूसरी ओर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है तथा ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति का वह इष्टतम दर क्या होगा, जो नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर केवल अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाले। वह स्थिति ही मुद्रास्फीति की इष्टतम दर कहलायेगी है। जिस दर से अर्थव्यवस्था की जीडीपी में वृद्धि हो और उसी दर से मुद्रास्फीति भी बढ़े। यह स्थिति ही मुद्रास्फीति की 'इष्टतम दर' कहलायेगी और इस स्थिति में मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण (Control over Inflation)

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिये दो नीतियों का अनुसरण किया जाता है—**प्रथम** मौद्रिक नीति व **द्वितीय** राजकोषीय नीति द्वारा।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण—मौद्रिक नीति द्वारा

मौद्रिक नीति का अर्थ—देश के केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्मित ऐसी नीति जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता को समायोजित किया जाता है, मौद्रिक नीति (Monetary Policy) कहलाती है। अर्थात् यह नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के साथ ही यह तय करती है कि आरबीआई किस दर पर बैंकों को कर्ज देगा या फिर किस दर पर उन बैंकों से पैसा वापस लेगा।

ध्यातव्य हो कि

वर्तमान में मौद्रिक नीति की नीतिगत दरों की घोषणा 'मौद्रिक नीति समिति' (Monetary Policy Committee—MPC) के द्वारा प्रत्येक दो माह में की जाती है। इस समिति में कुल 6 सदस्य (तीन केन्द्र सरकार द्वारा चयनित व शेष सदस्य आरबीआई से) होते है और समिति का अध्यक्ष आरबीआई का गर्वनर होता है।

मौद्रिक नीति की नीतिगत दरे—मौद्रिक नीति की प्रमुख नीतिगत दरों को परिवर्तित कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आरबीआई का प्रमुख कार्य है। यहाँ मौद्रिक नीति की नीतिगत दरे, उसका अर्थ व मुद्रास्फीति के नियंत्रण में उनकी भूमिका का क्रमबद्ध वर्णन किया जा रहा है—

तालिका 4.2: मौद्रिक नीति की नीतिगत दरें और उनका अर्थ

नीतिगत दरें	अर्थ	मुद्रास्फीति पर नियंत्रण
बैंक दर (Bank Rate)	जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है वह दर **बैंक दर** कहलाता है।	यदि आरबीआई पहले की तुलना में बैंक दर को बढ़ाती है तो व्यापारिक बैंको का आरबीआई से ऋण लेना महंगा हो जायेगा जिससे ये बैंक अपेक्षाकृत कम ऋण की मांग करेंगे और अर्थव्यवस्था में तरलता जाने से रूक जायेगी। यह स्थिति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक है। ***नोट***—यदि आरबीआई पहले की तुलना में बैंक दर को घटाती है तो उपरोक्त के विपरीत की स्थिति बनेगी अर्थात् अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी।
रेपो दर (Repo Rate)	जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है वह दर **रेपो दर** कहलाता है।	यदि आरबीआई पहले की तुलना में रेपो दर को बढ़ाती है तो व्यापारिक बैंक स्वत: ही आम जनता के लिये ब्याज दरे बढ़ा देते है। परिणामस्वरूप आम जनता बैंकों से दूरी बना लेते है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में तरलता जाने से रोक देती है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। ***नोट***—यदि आरबीआई पहले की तुलना में रेपो दर को घटाती है तो उपरोक्त के विपरीत की स्थिति बनेगी अर्थात् आम जनता बैंकों से अधिक मात्रा में तरलता प्राप्त कर मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।
रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)	व्यापारिक बैंक जिस दर पर अपनी अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास रखते है, वह दर **रिवर्स रेपो** दर कहलाता है। इस पर बैंकों को ब्याज की प्राप्ति होता है।	यदि आरबीआई पहले की तुलना में रिवर्स रेपो दर को बढ़ाती है तो व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास अधिक से अधिक मात्रा में अपनी अतिरिक्त तरलता रखने के लिए प्रेरित होंगे। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में तरलता जाने से रोक देगी। परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। ***नोट***—यदि आरबीआई पहले की तुलना में रिवर्स रेपो दर को कम करती है तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है और मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

(Continued)

तालिका 4.2: मौद्रिक नीति की नीतिगत दरें और उनका अर्थ *(Continued)*

नीतिगत दरें	अर्थ	मुद्रास्फीति पर नियंत्रण
नकद आरक्षण अनुपात (Cash Reserve Ratio [CRR])	व्यापारिक बैंक अपनी नकदी का एक निश्चित अनुपात (आरबीआई द्वारा निर्धारित) आरबीआई के पास रखते है, वह दर **नकद आरक्षण अनुपात** कहलाता है। इस पर ब्याज देय नहीं है।	यदि आरबीआई पहले की तुलना में सीआरआर की दरे बढ़ाता है तो प्रत्यक्ष रूप से बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में तरलता जाने से रोक देगी। परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति नियंत्रित होगा। ***नोट***—यदि आरबीआई पहले की तुलना में सीआरआर के दर को कम करता है तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है और मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। सीआरआर मुद्रास्फीति नियंत्रण करने का सबसे बेहतर उपकण है।
सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio [SLR])	व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात स्वर्ण, नकद और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। यह अनुपात ही **सांविधिक तरलता अनुपात** कहलाता है।	यदि आरबीआई पहले की तुलना में एसएलआर की दरे बढ़ाती है तो बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक बड़ा हिस्सा स्वर्ण, नकद व सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होगा, जिससे बैंकों की तललता अर्थव्यवस्था में नहीं पहुँच पाती और यह स्थिति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक है। ***नोट***—यदि आरबीआई पहले की तुलना में एसएलआर की दरे कम करता है तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ने की संभावनाये बढ़ जाती है और यह स्थिति मुद्रास्फीति की स्थिति को जन्म दे सकती है।
सीमांत स्टेन्डिंग सुविधा (Marginal Standing Facility [MSF])	9 मई 2011 से प्रारम्भ आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली ऐसी सुविधा है जिसके तहत बैंक अपने शुद्ध मांग और सावधि उत्तरदायित्व का 2 प्रतिशत तक अति अल्प अवधि रातों रात के लिए ऋण ले सकते हैं। एमएसएफ के तहत व्यापारिक बैंक एसएलआर के तहत रखी प्रतिभूतियों के बदले भी उधार ले सकते हैं। जिस दर पर बैंक, आरबीआई से उधार लेगें, वहीं दर एमएसएफ कहलाता है। ***नोट***—एमएसएफ की दरें रेपो दर से सैदव एक प्रतिशत अधिक ही होगी।	यदि आरबीआई पहले की तुलना में एमएसएफ की दरे बढ़ाती है तो बैंक ऋण लेने से दूर ही रहेंगे और अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता न पहुंचने से मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगी। ***नोट***—यदि आरबीआई पहले की तुलना में एमएसएफ की दरे घटाती है तो उपरोक्त स्थिति के विपरीत की स्थिति बनेगी अर्थात् तरलता बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मौद्रिक नीति की विभिन्न नीतिगत दरें जैसे—बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर और एमएसएफ की दरे बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में तरलता नियंत्रित होती है और परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की बढ़ी हुई दरे भी नियंत्रित होती है, जबकि इसके विपरीत नीतिगत दरों में कमी/कटौती अर्थव्यवस्था में तरलता, वृद्धि करने में सहायक है। इस प्रकार जब आरबीआई नीतिगत दरों को बढ़ाती है तो वह स्थिति **सख्त मुद्रा नीति** (Dear/Strong Money Policy) कहलाती है, जबकि नीतिगत दरों में कमी, **सस्ती मुद्रा नीति** (Cheap Money Policy) कहलाती है। आरबीआई अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप कभी सख्त मुद्रा नीति और कभी सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण करती है।

खुला बाजार प्राचलन और मुद्रास्फीति नियंत्रण

आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय 'खुला बाजार प्राचलन' कहलाता है। यह प्रक्रिया भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक है क्योंकि जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय (बेचती) करती है तो अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी दृष्टिगोचर होती है जबकि इसके विपरीत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय (खरीदती) करती है तो

अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाती है। अर्थात खुला बाज़ार प्राचलन, मौद्रिक नीति का ही उपकरण है।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण—राजकोषीय नीति द्वारा

राजकोषीय नीति का अर्थ—सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबन्धन से सम्बन्धित नीति, राजकोषीय नीति कहलाती है। सरकार 'सार्वजनिक व्यय' सामाजिक तथा मेरिट वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति हेतु करती है इसलिए सार्वजनिक व्यय को राज्य का प्रारम्भ बिन्दु कहते है। शेष सभी (करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबन्धन) इस क्रिया को पूरा करने के साधन मात्र है। राजकोषीय नीति को ही बजेटरी नीति भी कहते हैं।

राजकोषीय नीति भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जो कि निम्नवत् हैं—

करारोपण द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण—यदि सरकार अपनी राजकोषीय नीति के उपकरण 'करारोपण' की दरो को बढ़ाती है तो आम जनता की 'व्यय योग्य आय' में स्वत: ही कमी हो जाती है। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में सापेक्ष मांग कम होने लगती है और यह स्थिति एक ओर मांग और पूर्ति के मध्य अंतर को कम कर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकती है वहीं दूसरी ओर सरकार को पहले की तुलना में कर राजस्व अधिक प्राप्त होता है जिसे वह पूर्ति पक्ष को बढ़ाने में व्यय करती है। इस प्रकार राजकोषीय नीति के उपकरण करारोपण (Taxation) के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

करारोपण की दरे एक सीमा तक बढ़ा कर मुद्रास्फीति नियंत्रित करना कारगर है, परन्तु एक सीमा से अधिक करारोपण की दरे बढ़ाना अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि बढ़ी हुई कर की दरें एक ओर कर चोरी की प्रवृत्तियों को बढ़ाने में सहायक है जिससे सरकार को प्राप्त होने वाले कर राजस्व में गिरावट दृष्टिगोचर होगा तो वहीं दूसरी ओर बढ़ी हुई कर की दरें निवेशक वर्ग को निवेश के लिए हतोत्साहित करेगी जिससे प्रत्यक्ष रूप से देश की जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।

सार्वजनिक ऋण द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण—राजकोषीय नीति का अहम उपकरण 'सार्वजनिक ऋण' है। जिसके अन्तर्गत सरकार विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर (सरकारी प्रतिभूति, ईपीएफ, जीपीएफ) आम जनता से ऋण लेती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता खिंचकर सरकार के पास पहुंच जाती है। अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित कर मांग को प्रत्यक्ष रूप से कम किया जा सकता है। यह स्थिति पुन: मांग और पूर्ति के मध्य अंतर को कम कर वस्तु की मूल्य वृद्धि होने से रोक देती है। अत: यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक ऋण मुद्रास्फीति की बढ़ी हुई दरें नियंत्रित करने में सहायक है।

सार्वजनिक ऋण भी एक सीमा तक ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कारगर है क्योंकि जागरूकता के अभाव व सरकार को ऋण देना बाध्यकारी न होने के कारण, अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता बनी रहती है, जो मांग और पूर्ति पक्ष के मध्य अंतर को बनाये रखती है।

सार्वजनिक व्यय में नियंत्रण द्वारा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण—सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष बजट बनाकर भारी-भरकम व्यय करती है, यह व्यय सरकार के लिये अनिवार्य है। इन व्ययों में शामिल है—रक्षा, स्वास्थ्य, सब्सिडी, प्राइमरी शिक्षा, प्रशासनिक सेवा जैसे क्षेत्र। इन व्ययों के साथ ही साथ सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर भी बड़ी मात्रा में व्यय करती है, जिनकी प्रकृति गैर-उत्पादक है। ऐसे व्यय अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता की समस्या बनाए रखते है यह अतिरिक्त तरलता मांग में, पूर्ति के सापेक्ष अधिक तीव्रता से वृद्धि करती है अर्थात् बढ़े हुए गैर-उत्पादक व्यय, तरलता में वृद्धि कर मुद्रास्फीति की दरें बढ़ी हुई बनाये रखने में सहायक है। यदि सरकार गैर-उत्पादक गतिविधियों में किये जाने वाले सार्वजनिक व्ययों को चरणबद्ध तरीके से कम करती है और उन व्ययों को आपूर्ति पक्ष को बढ़ाने में व्यय करें तो यह स्थिति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कारगर सिद्ध होगी।

इस प्रकार राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हुए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भरसक प्रयास करते हैं।

अध्याय सार संग्रह

- जब बाजार मे मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाती है तो वस्तुओं के मूल्यों मे कमी और मुद्रा की क्रय क्षमता मे वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति मे उत्पादक वर्ग को हानि होती है परिणामस्वरूप निवेश, रोजगार एवं आय में कमी आने लगती है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है, यह स्थिति ही '**मुद्रा संकुचन**' (Deflation) कहलाती है।
- मुद्रा संकुचन एवं मंदी के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा कृत्रिम रूप से नकदी को बढ़ा कर, वस्तुओं की मांग को प्रेरित करने की स्थिति ही 'रिफ्लेशन' कहलाती है अर्थात् कृत्रिम रूप से मुद्रास्फीति को बढ़ाना **रिफ्लेशन** कहलाता है।
- रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है जब पूर्ति की तुलना में मांग कम हो, तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति मे धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है और उत्पादित वस्तुएं बिना बिके रह जाती है इससे उद्योगों को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ती है।

- सस्ती मुद्रा नीति से अभिप्राय ऐसी मौद्रिक नीति से है जिसके अंतर्गत उद्योगों, व्यवसायों व उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर व आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध होता है अर्थात् उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु जिस नीति का अनुसरण आरबीआई करती है '**सस्ती मुद्रा नीति**' कहलाती है।
- आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाती है ताकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त नकद द्रव्य न पहुंच सके, '**महंगी मुद्रा नीति**' कहलाती है।
- आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का 'क्रय–विक्रय' खुला बाजार प्राचलन कहलाता है।
- सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण सम्बन्धी क्रियाओं तथा प्रबन्ध से सम्बन्धित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। इस नीति में मुख्य रूप से तीन मुद्दे शामिल होते हैं—(i) करारोपण (Taxation), (ii) सार्वजनिक ऋण (Public Borrowing), (iii) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)।
- मुद्रासंकुचन, मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति है। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन दोनों के ही अपने गुण तथा दोष हैं। दोनों से ही अर्थव्यवस्था में अस्थिरताएं उत्पन्न करती है। केन्स (Keynes) के अनुसार, 'स्फीति अनुचित तथा न्याय विरूद्ध है जबकि अवस्फीति अनुपयुक्त है।' केन्स के अनुसार, अवस्फीति ज्यादा हानिकारक है स्फीति से। वे कहते हैं कि स्फीति अनुचित है, क्योंकि यह आय तथा संपत्ति की असमानताएं उत्पन्न करती है। गरीब वर्ग को हानि होने पर, अमीर वर्ग को लाभ होता है। अवस्फीति के दौरान, देश की राष्ट्रीय आय घट जाती है। बेरोजगारी बढ़ती है तथा हड़ताले (Lay Off) तथा तालाबन्दी (Lockout) होती है।
- स्फीति एक लाभकारी स्थिति है क्योंकि इससे आर्थिक क्रियाएं बढ़ती है तथा रोजगार की उपलब्धता में वृद्धि होती है। उत्पादकों को असामान्य लाभ अर्जित होता है। इससे अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्र मे समृद्धि आती है। अवस्फीति हानिकारक स्थिति है क्योंकि उत्पादक वर्ग को ही हानि होती है तथा उनका लाभ शून्य होता है। स्टाक बिना बिका होने के कारण उत्पादन स्तर में गिरावट आती है। इससे अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्र मे उदासीनता तथा मंदी आती है।
- एक देश पर बुरा प्रभाव तब पड़ता है जब अवस्फीति मंदी मे परिवर्तित हो जाती है। इससे गरीबी, भूख तथा दु:ख फैलते है। स्फीति तथा अवस्फीति दोनों ही बुराइयां है परन्तु अवस्फीति एक बड़ी बुराई है, ऐसा इसलिए क्योंकि स्फीति को अवस्फीति की तुलना मे नियंत्रित किया जा सकता है।